

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 465

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 07 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

फेम इंडिया योजना का नया चरण

465. श्री संजय सेठ:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने फेम (एफएएमई) इंडिया पहल को प्रभावकारी बनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बंगलुरु इत्यादि जैसे बड़े शहरों में सड़क किनारों पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार फेम इंडिया योजना का नया चरण प्रारंभ करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) दो-पहिया और चार-पहिया वाहन खंड में क्रमशः सर्वाधिक सफल वाहनों संबंधी आंकड़े क्या हैं और उनसे संबंधित मौद्रिक प्रोत्साहन क्या-क्या हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) से (ग): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भारी उद्योग विभाग ने [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] फेम इंडिया योजना तैयार की। इस समय, चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग सृजन, प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से फेम इंडिया योजना का चरण-I कार्यान्वयन के अधीन है। फेम इंडिया योजना के चरण-I को मूलतः दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अनुमत है।

फेम इंडिया योजना के चरण-II में बाजार सृजन और मांग संग्रह के द्वारा ईवी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने तथा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। मसौदा योजना में चार्जिंग अवसंरचना, ईवी प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास और अधिक स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के प्रावधान सहित ईवी उद्योग के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

फेम इंडिया योजना के चार्जिंग अवसंरचना फोकस क्षेत्र के तहत सरकार ने चार्जिंग अवसंरचनाओं/स्टेशनों की स्थापना हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं/प्रस्ताव मंजूर किए हैं:

क्र.सं.	परियोजना/प्रस्ताव का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी/संगठन
1.	बंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क (25 डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना)	लिथियम अर्बन टेक्नालॉजिज प्रा. लि. के सहयोग से मै. महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स प्रा. लि.
2.	ईवी के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर
3.	ईवी के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
4.	दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव (150 एसी और 50 डीसी वाले चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर

हाल ही में जनवरी, 2019 माह में, दिल्ली-जयपुर-दिल्ली, मुंबई-पुणे-मुंबई, दिल्ली-चंडीगढ़-दिल्ली राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आरईआईएल और भेल से प्राप्त प्रस्तावों को भी फेम इंडिया योजना के तहत मंजूर किया गया है।

योजना के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन के क्रेता को इसके व्यापक अंगीकरण को समर्थ बनाने हेतु एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में छूट दी जाती है। इस समय, फेम इंडिया योजना के तहत प्रति वाहन ₹22,000/- की दर से आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पांच (5) मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) ने इलेक्ट्रिक दुपहियों के ग्यारह (11) मॉडलों को पंजीकृत कराया है। इसी प्रकार, प्रति वाहन ₹70,000/-, ₹1,24,000/- और ₹1,38,000/- की दर से आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत पांच (5) ओईएम के इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों के इक्कीस (21) मॉडल पंजीकृत हैं।
